खंड स्तर पर ग्रामीण कारीगरों के लिए योजना का विनियोजन तथा क्रियान्वयन

1019. **श्री केयूर भूषण :** क्या ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खंड स्तर पर ग्रामीण कारीगरों के लिए योजनाओं के विनियमन तथा क्रियान्वयन की क्या स्थिति है तथा उनमें खादी ग्रामोद्योग और हस्तशिल्प बोर्ड क्या सहयोग दे रहा है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री बालेश्वर राम) : ग्रामीण कारीगरों को इनके द्वारा सहायता पहुंचाई जा रही है :—

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिए जा रहे ग्रामीण उद्योगों, सेवाओं तथा व्यापार उद्यमों के कार्यक्रम । 31—3—1981 को लाभभोगियों की कुल संख्या 2,68,378 थी ।

(2) ग्रामीण युवकों के लिए स्वरोजगार की योजना (ट्राइसेम) जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों से सम्बद्ध कुशलता तथा औद्योगिकी और स्वरोजगार के लिए तैयार करने की व्यवस्था है । 31—3—81 तक अन्तर्गत लाए गए युवकों की संख्या 1,46,706 थी ।

(3) कारीगरों की कुशलताओं तथा अन्य अपेक्षित निवेशों को सुलभ करने वाला खादी तथा ग्रामोद्योगों का कार्यक्रम । 31-3—1981 तक कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 लाख व्यक्तियों को लाया गया था ।

(4) हस्तशिल्प बोर्ड कारीगरों के उत्पादों की बिक्री के लिए खण्ड विकास स्तर पर ग्रामीण विपणन केन्द्र स्थापित कर रहा है । 31—3—1980 तक विभिन्न खंडों के लिए इस प्रकार के लगभग 200 केन्द्रों को मंजूरी दे दी गई है ।

Destruction of trees due to extraction of resin

1020. SHRI R. P. GAEKWAD: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that excessive extraction of resin has resulted in destruction of trees and the large areas exposed to perils of land-slides and erosion in Himalayas in Uttar Pradesh and Jammu & Kashmir, and

(b) if so, the steps proposed to be taken to check the peril of denudation in these areas?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R V. SWAMINATHAN): (a) and (b). The requisite information is being collected from the concerned State Governments and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Diversification functions of F.C.I.

1021 SHRI K T. KOSALRAM Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether the plans for diversification of the functions of the Food Corporation of India undertaken in 1975 have since been given up and if so, the reasons thereof;

(b) the year-wise and region-wise statistics of procurement of foodgrains during the past five years; and

(c) the steps being taken to revitalise the Food Corporation of India so that the annual target of foodgrains procurement is achieved?